न्यू पेंशन स्कीम : हर महीने 1600 से 5000 रु. तक फायदा

सरकार एनपीएस खाते में 10 के बजाय 14% राशि जमा करेगी

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

प्रदेश के न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) वाले 4 लाख अफसरों और कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में अपने अंशदान की राशि 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दी है। इससे कर्मचारियों को हर महीने 1600 रुपए और अफसरों को 5000 रुपए तक का फायदा होगा। मंगलवार को हुई वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग इसका फैसला हुआ। बढ़ी हुई चार फीसदी राशि 1 अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में डाली जाएगी। इससे सरकार पर हर महीने लगभग 80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का अनुसमर्थन कर दिया है। इसके तहत आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के 250 अस्पतालों में लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद सेवा में आने वाले अफसरों और कर्मचारियों के लिए एनपीएस स्कीम लागू की गई है। इसमें 2 लाख अफसर, कर्मचारी और 2 लाख शिक्षक हैं। इनके वेतन से हर महीने 10 फीसदी राशि कर्मचारी के वेतन से काटी जाती है और इतना ही अंश राज्य सरकार मिलाती है।

Badri Gautam

हर माह वेतन से कटेंगे 200 रुपए

प्रदेश के 2.87 लाख शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ

◆ रिटायर होने पर ब्याज के साथ बीमा की राशि दी जाएगी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों को भी सामूहिक बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण सहित अन्य किसी कारण से अगर शिक्षक की मृत्यु होती है, तब भी उसके परिवार को बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए शिक्षक के वेतन से हर माह 200 रुपए काटे जाएंगे। अगर शिक्षक जीवित रहते हैं तो रिटायर होने पर ब्याज के साथ बीमा की राशि दी जाएगी। इस निर्णय के बाद प्रदेश भर के 2 लाख 87 हजार शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

1 जुलाई 2018 और इसके बाद नियुक्त शिक्षक भी शामिल

लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि विभाग की शैक्षणिक शालाओं में 1 जुलाई 2018 एवं इसके बाद नवीन शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्त होने के बाद सामूहिक बीमा योजना के तहत राशि का कटोत्रा किया गया है तो ऐसे नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ नियमानुसार शीघ्र दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पांच लाख और ढाई लाख की बीमा राशि

योजना के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षक का 5 लाख का और माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक का ढाई लाख का बीमा किया जाएगा। शिक्षक की मृत्यु की स्थिति में उच्च माध्यमिक शिक्षक के परिवार को 5 लाख रुपए और माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के परिवार को ढाई लाख रुपए दिए जाएंगे।

Badri Gautam

सीबीएसई

स्कूलों को 11 जून तक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे 10वीं के मार्क्स

सिटी रिपोर्टर| सीबीएसई ने 10वीं के मार्क्स अपलोड करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया है। स्कूल ऑल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम के मुताबिक 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के मार्क्स ई-परीक्षा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स को हर विषय के लिए 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे। इनमें 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट से दिए जाएंगें और 80 मार्क्स साल भर में आयोजित अलग-अलग परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। एक बार स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड के बाद इसे एडिट या मॉडिफाई नहीं किया जा सकेगा। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को 11 जून तक या उससे पहले 10वीं कक्षा के छात्रों के अंक अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इस साल 10वीं के स्टूडेंट्स का रिजल्ट 20 जून तक जारी करेगा।

Badri Gautam

बेंचमार्क के आधार पर बनेगा 10वीं का रिजल्ट, तैंतीस फीसदी पर पास होंगे फेल विद्यार्थी

दसवीं के 11 लाख विद्यार्थियों की नहीं होगी परीक्षा, कोरोना के संक्रमण में कमी आने के बाद होगी बारहवीं की परीक्षा, मंत्री के पास पहुंचा प्रस्ताव, दो-तीन में जारी होंगे आदेश

नीरज गौर, भोपाल

प्रदेश में अब दसवीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। दसवीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट बेंचमार्क के आधार पर बनेगा। इसमें विद्यार्थियों को स्कूल के तीन साल के रिजल्ट के आधार पर अंक दिए जाएंगे। फेल होने वाले विद्यार्थियों को तैंतीस फीसदी पर पास किया जाएगा। वहीं, बारहवीं की परीक्षा कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग का दसवीं-बारहवीं के विद्यार्थियों की परीक्षा को लेकर प्रस्ताव मंत्री इंदर सिंह परमार के पास पहुंच गया है। परीक्षा को लेकर दो-तीन में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीस अप्रैल से शुरू होने वाली दसवीं की परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग स्थगित कर चुका है। अब सिर्फ बारहवीं की परीक्षा होगी। दसवीं के विद्यार्थियों को

एमपी बोर्ड द्वारा सीबीएसई की तर्ज पर जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्पष्ट कर दिया है कि दसवीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मापदंड पर विचार किया जा रहा है। इसमें सभी विद्यार्थियों को मार्कशीट में अंक दिए जाएंगे। विभागीय सूत्रों की माने तो नियमित विद्यार्थियों का रिजल्ट बेंचमार्क के आधार पर बनेगा। इसके तहत प्रायवेट स्कूलों का तीन साल का रिजल्ट देखा जाएगा। तीन साल के सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट के आधार पर विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार होगा।

फेल होने वाले विद्यार्थियों को तैतीस फीसदी पर किया जाएगा पास

दसवीं की परीक्षा में विद्यार्थियों को रिजल्ट बनाने के दौरान विद्यार्थी फेल हो जाते है, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को तैतीस फीसदी अंक देने का प्रस्ताव भी दिया गया है। मंत्री के पास पहुंचे प्रस्ताव में दसवीं के प्रायवेट विद्यार्थियों के लिए दो आप्शन रखे गए है। पहला इन सभी विद्यार्थियों को तैतीस फीसदी अंक देकर सिर्फ पास कर दिया जाए। दूसरा कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद इन विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाए। दोनों प्रस्ताव या इसमें एक पर पंद्रह मई के पहले मंत्री द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद होगी परीक्षा

दसवीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट बनाने के साथ मंडल ने परीक्षा का प्रस्ताव भी रखा है। इसके तहत बेंचमार्क के आधार पर विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस रिजल्ट पर किसी विद्यार्थी को आपत्ति है, तो कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हो सकता है। मंडल द्वारा परीक्षा लेकर विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दसवीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट बनाने में स्कूल प्रबंधन भेदभाव नहीं कर सकता है। मंत्री का पास पहुंचे प्रस्ताव में विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुसार ही अंक मिलेंगे। इसमें स्कूल के तीन साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट के साथ विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन में मिले नंबर के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

मंडल की दसवीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा। इसके लिए मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव पर अध्ययन किया जा रहा है। पंद्रह मई के पहले दसवीं के रिजल्ट को लेकर आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) मप्र शासन

Pdfcreator

दो लाख शिक्षकों को समूह बीमा योजना का मिलेगा लाभ

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। शासन द्वारा राज्य सेवा संवर्ग में शामिल शिक्षकों को समूह बीमा योजना का लाभ देने का आदेश दिया है, जबकि पहले से ही इन्हें लाभ मिल रहा है। जिन शिक्षकों के कोषालय से एम्पलाई कोड जारी नहीं हुए है। उन शिक्षकों को समूह बीमा योजना का लाभ कैसे मिल पाएगा। इसका स्पष्ट उल्लेख स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश किया गया है।

बता दें कि प्रदेश के दो लाख 37 हजार अध्यापक संवर्ग को राज्य शिक्षा सेवा कैडर में शामिल किया गया था। इसमें से दो लाख शिक्षकों को समूह बीमा का लाभ मिलेगा, जबकि शेष शिक्षकों का एम्पलाई कोड नहीं बनने से वे योजना से वंचित रह जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री कियावत ने आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि नए शैक्षणिक संवर्ग

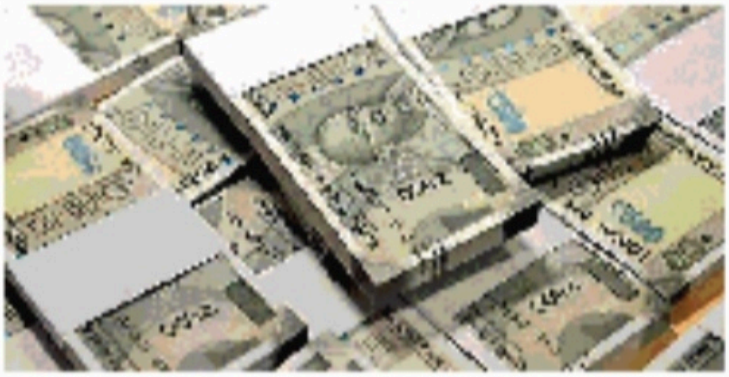

में नियुक्त शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ शीघ्र दिया जाए। वहीं शासकीय अध्यापक संघ के प्रदेश संयोजक उपेंद्र कौशल ने मांग की है कि सभी शिक्षकों का एम्पलाई कोड बनाकर समूह बीमा योजना का लाभ दिया जाए। हर माह 200 से 400 रुपये की होती है कटौती राज्य शिक्षा सेवा कैडर में नियुक्त प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक का बीमा राशि के रूप में प्रतिमाह 200 रुपये और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का 400 रुपये प्रतिमाह वेतन से कटता है। इसमें प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों के लिए ढाई लाख रुपये और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पांच लाख रुपये का बीमा निर्धारित है।

Badri Gautam

इंजीनियरिंग कॉलेज 31 अगस्त तक काउंसिलिंग पूरी करने के हैं निर्देश

15 सितंबर से नए सत्र की कम संभावना

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने सभी इंजीनियरिंग कालेजों की कक्षाएं 15 सितंबर से शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। 15 सितंबर से सिर्फ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाने के लिए कहा गया है। वहीं अब तक कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए अभी बारहवीं की परीक्षा कराना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगर जून में परीक्षा होती है तो अगस्त तक रिजल्ट घोषित होगा। ऐसे में एडमिशन प्रक्रिया सितंबर से शुरू होने की संभावना है, जबकि एआइसीटीई ने प्रथम राउंड की काउंसिलिंग 31 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं, जो कि संभव नहीं है। वहीं पिछले साल इंजीनियिरिंग कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया जनवरी 2021 तक चला था। ऐसे में इस साल सितंबर से सत्र कक्षाएं शुरू करना संभव नहीं है। इसे लेकर एसोसिएशन ऑफ टेक्नीकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स (एआइसीटीई) ने एआइसीटीई को पत्र लिखकर विचार करने के लिए कहा है।

छह माह पीछे चल रहा है पिछला सत्र: पिछला सत्र 2020-21 ही छह महीने पीछे चल रहा है। ऐसे में सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं भी देर से हो रही है। वहीं कई राज्यों की बारहवीं की परीक्षाएं अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में दूसरे राज्यों के विद्यार्थी एडमिशन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे।

> अभी कई राज्यों की बारहवीं की परीक्षाएं नही हो पाई है। पिछला सत्र ही पीछे चल रहा है। ऐसे में एआइसीटीई को पुर्नविचार कर फिर से समय-सारिणी जारी करना चाहिए।
>
> – **अजीत पटेल**, मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष, एटीपीआई

कोरोना की जंग सभी को मिलकर जीतना होगी

भोपाल, नवदुनिया रिपोर्टर)। द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के ह्युमेनिटीस डिपार्टमेंट द्वारा इंटरनेशनल वेबिनार बैटलिंग विद कोविड का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में अमेरिका के वर्जिनिया और वाशिंगटन डीसी में स्माइल एक्सपर्ट डेंटल की फाउंडर डॉ अंदलीब रहमान और ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस, दिल्ली की डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की सीनियर रेजीडेंट डॉ क्षितिजा सिंह जैन मुख्य वक्ता थीं। डॉ अंदलीब रहमान ने यूएस के हालातों को साझा करते हुए बताया कि कोरोना एक युद्ध है और इस युद्ध में हम तभी जीत सकते हैं जब हम सब मिलकर मजबूती से लड़ें और इसके बचाव के लिए सुरक्षित शारीरिक दूरी बहुत-बहुत जरूरी है।

Badri Gautam

बीयू : सेंट्रल जेल में बनेगा परीक्षा केंद्र, सवा सौ परीक्षार्थी होंगे शामिल

ओपन बुक सिस्टम से देंगे एग्जाम, यूजी-पीजी के साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करने वालों की परीक्षा को लेकर शुरू की तैयारियां

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से यूजी-पीजी परीक्षाओं को लेकर दिशा-निर्देश जारी होने के बाद बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) ने ओपन बुक सिस्टम के तहत परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बीयू जून और जुलाई में यूजी-पीजी के साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं लेगा। इसके लिए सेंट्रल जेल को एग्जाम सेंटर बनाया गया हैं। इन परीक्षाओं में करीब तीन लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।

प्रिंट करवाकर देंगे पेपर

बीयू ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं लेगा, इसलिए विद्यार्थी विवि के वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर हल कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल जेल में पेपर डाउनलोड करने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। ऐसे में जेल में बंद विद्यार्थियों तक पेपर पहुंचाना मुश्किल होगा। ऐसे में बीयू प्रशासन ने विद्यार्थियों के संख्या के तहत पेपर प्रिंट कराकर जेल में पहुंचाने की व्यवस्था की है। इसे पढ़कर कॉपियों को भी जमा करने की व्यवस्था की जाएगी।

जेल में सवा सौ कैदी ओपन बुक पद्धति से देंगे परीक्षा

परीक्षा के लिए करीब 315 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही इस बार सेंट्रल जेल को भी एग्जाम सेंटर बनाया गया है। जहां करीब सवा सौ कैदी ओपन बुक पद्धति से परीक्षा देंगे। इसमें यूजी-पीजी के अलावा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के विद्यार्थी भी शामिल हैं। बता दें कि बीयू के बीए, बीकॉम, बीएससीए होमसाइंस, बी, मैनेजमेंट, बीबीए, बीसीए, बीकॉम आनर्स की यूजी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की मुख्य वार्षिक एवं पूरक परीक्षा के फार्म विद्यार्थी 20 मई तक ऑनलाइन भर सकेंगे। 21 मई को विद्यार्थी 300 रुपए विलंब शुल्क के साथ फार्म जमा कर सकेंगे।

व्यापमं : विद्यार्थियों को पीपीटी का शुल्क वापस करने की तैयारी

गत वर्ष प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट (पीपीटी) निरस्त होने के बाद अब व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने 21 हजार विद्यार्थियों के पचास लाख रुपए वापस करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए व्यापमं को करीब 75 फीसदी विद्यार्थियों के एकाउंट नंबर और जानकारी व्यापमं तो मिल चुके हैं, लेकिन शेष 25 फीसदी विद्यार्थियों की बैंक संबंधी मौजूद नहीं हैं। ऐसे में अब व्यापमं इन 25 प्रतिशत विद्यार्थियों का डेटा लेने के लिए अपनी वेबसाइट पर दोबारा से लिंक खोलेगा, जिसके बाद विद्यार्थियों को शुल्क वापस किया जाएगा।

10वीं-12वीं पर एक-दो दिन में फैसला!

कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावित हुई माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं के परीक्षा को लेकर एक दो दिन में फैसला हो सकता है। मंडल के सचिव उमेश कुमार सिंह की ड्यूटी बंगाल चुनाव में लगाई गई थी, वह वहां से लौट आए हैं। ऐसे में मंडल के सूत्रों की माने तो 10वीं के वैल्यूएशन पैटर्न और 12वीं के एग्जाम पैटर्न पर एक दो दिन में फैसला हो सकता है। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट कैसे तय होगा। इस पर अभी तक विचार चल रहा है। वहीं अब सिर्फ 12वीं की परीक्षा की बात कही जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही स्पष्ट कर कर चुका है कि दसवीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मापदंड पर विचार किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 10वीं परीक्षा के मूल्यांकन के लिए विकल्प तय करने की जिम्मेदारी दी है। 15 मई से पहले निर्णय होने की संभावना है।

Bauer Gautam

पेंशन योजना में चार फीसद बढ़ेगा सरकार का अंशदान

कर्मचारियों को राहत ● मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय

10 फीसद अंशदान दिया जा रहा था अभी तक योजना में

14 फीसद हो जाएगा सरकार का अंशदान अब

600 करोड़ रुपये का आएगा सालाना वित्तीय भार

भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। प्रदेश में 2005 के बाद भर्ती हुए 4.49 लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन योजना में सरकार अपना अंशदान चार फीसद बढ़ाएगी। अब यह 14 प्रतिशत होगा। इस कदम से सरकार पर सालाना लगभग छह सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्तवित्तीय भार आएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। अभी प्रदेश में आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों के लिए सरकार 14 प्रतिशत अंशदान ही दे रही थी। उधर, पिछले साल किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए चमकविहीन गेहूं के बदले में सरकार राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 31 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करेगी।

कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विधायक जुगल किशोर बागरी, बृजेंद्र सिंह राठौर और कलावती भूरिया के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ जिलों को छोड़कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को लेकर भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की समिति भी बनाई है।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को वर्चुअल कैबिनेट बैठक हुई। ● **जनसंपर्क विभाग**

वहीं, ब्लैक फंगस को लेकर भी अलग से समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में सरकार का अंशदान 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। इससे नियमित के साथ अध्यापक, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को फायदा होगा। किसानों के लिए आगामी वर्षों में यूरिया, डीएपी, पोटाश, सुपर फास्फेट सहित अन्य खाद का इंतजाम करने करने के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी बनाया गया है। खाद का अग्रिम भंडारण भी पहले की तरह किया जाएगा। राज्य एवं जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों के संविलियन के लिए योजना को 30 जून तक बढ़ाने और नर्मदा वेसिन कंपनी को डेढ़ हजार करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जारी करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को लागू करने के निर्णय का अनुसमर्थन करते हुए बताया गया कि इसमें प्रदेश की 88 प्रतिशत आबादी शामिल है।

कोरोना योद्धा के लिए बनेगी एक जैसी योजना: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे सभी कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। विभागों की अलग-अलग योजना नहीं होगी। सबके लिए एक समान कोरोना योद्धा योजना बनाई जा रही है। सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

एक करोड़ टन गेहूं खरीदा: मुख्यमंत्री ने बैठक से पहले मंत्रियों को बताया कि कोरोना संक्रमण के बीच समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद जारी है। अब तक एक करोड़ टन गेहूं खरीदा जा चुका है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में अब महानिदेशक की जगह उपाध्यक्ष का पद होगा। संस्थान के उपाध्यक्ष ही राज्य नीति एवं योजना आयोग के भी पदेन उपाध्यक्ष होंगे। संस्थान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक पद और अतिरिक्तमुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक पद बनाया गया है।
- केंद्र सरकार की कृषि विस्तार योजना के तहत प्रदेश में कृषक मित्र चयन के लिए न्यूनतम आयु सीमा अब 40 वर्ष की जगह 25 वर्ष होगी।
- सोयाबीन प्र-संस्करण प्लांट, पचामा, सीहोर के प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रैप के रूप में 7.58 करोड़ रुपये में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने की अनुमति।
- कॉस्मो आनंद, सिरोल, ग्वालियर स्थित राजस्व विभाग के पांच भूखंड और अल्फा नगर कॉलोनी स्थित परिसंपत्ति अधिकतम निविदा वाली मूल्य का सौ फीसद जमा करने के बाद रजिस्ट्री की कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर अधिकृत।

Badri Gautam

कैदियों की परीक्षा ओपन बुक पद्धति से लेगा बीयू

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) की यूजी और पीजी की परीक्षाएं जून व जुलाई में होंगी। तीन लाख विद्यार्थी इस बार ओपन बुक पद्धति से परीक्षा देंगे। इसके लिए विवि ने 315 नोडल केंद्र बनाए हैं। इस व्यवस्था के चलते विश्वविद्यालय प्रबंधित सेंट्रल जेल में बंद करीब सवा सौ विद्यार्थियों की परीक्षा भी ओपन बुक पद्धति से ही लेगा। इसके लिए सेंट्रल जेल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहां कोरोना गाइडलाइन और जेल मुख्यालय के आदेश के तहत ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। विवि ओपन बुक पद्धति से परीक्षा लेने के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रश्नपत्र अपलोड करेगा। जहां से विद्यार्थी पेपर डाउनलोड कर हल कर सकते हैं। उधर, बीयू जून और जुलाई में ही यूजी-पीजी के साथ डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं लेगा।

Badri Gautam

विद्यार्थियों को मिली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की जानकारी

जबलपुर। नईदुनिया रिपोर्टर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बायोडिजाइन इनोवेशन सेंटर व इंस्टा प्रिंटस एजुकेशन इंदौर द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कपिल देव मिश्र ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप से प्रो. एसएस संधू निदेशक, बायोडिजाइन इनोवेशन सेंटर शामिल रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को इनोवेशन व टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी प्रदान करना था। जिससे छात्र- छात्राएं टेक्नोलॉजी व इनोवेशन के माध्यम से राष्ट्रहित में अपना योगदान दे सकें। विद्यार्थियों के अच्छे भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है कि वे तकनीक का उपयोग करके समाजोपयोगी कार्य करें। जिससे देश के साथ- साथ स्वयं विद्यार्थियों को भी बेहतर करियर के अवसर मिल सकते हैं। वेबिनार में कार्यक्रम में डी.पी.एस, मंडला रोड जबलपुर की प्रधानाध्यापक अपर्णा चौबे भी शामिल रहीं। इस कार्यक्रम में 280 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। कार्यक्रम के अंत में, प्रतीक संचेती, सी ई ओ, इंस्टा प्रिंटज एजुकेशन, इंदौर द्वारा सभी का धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम का संचालन अंकित रजक, मेंटर ऑफ चेंज, अटल इनोवेशन मिशन द्वारा किया गया।

Badri Gautam

बीयू : ओपन बुक परीक्षा में प्राइवेट के 42 हजार विद्यार्थी होंगे शामिल

भोपाल(आरएनएन)। कोरोना के हालात को देखते हुए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय अपनी सभी परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से लेगा। जिसके तहत प्रथम व दूसरे वर्ष की परीक्षाएं जुलाई में होंगी। लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जून में कराई जाएंगी। पूरी परीक्षा में करीब दो लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। यूजी.पीजी की ओपन बुक सिस्टम से होने वाली परीक्षाओं की कॉपियां विश्वविद्यालय राजधानी सहित प्रदेश भर के आठ जिलों में बनाए गए 225 केंद्रों पर जमा कराएगा। बीयू नियमित विद्यार्थियों के साथ ही प्राइवेट परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से कराएगा। प्रथम से तीसरे वर्ष की प्राइवेट परीक्षा में करीब 42 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। जिसमें से प्रथम वर्ष की प्राइवेट परीक्षा में करीब साढ़े 12 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे जबकि दूसरे और तीसरे वर्ष में करीब तीस हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। इस सत्र में कोरोना संक्रमण के कारण प्राइवेट परीक्षा में गत वर्ष की अपेक्षा करीब तीन हजार आवेदन कम जमा हुए हैं। बीयू द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षा के लिए आवेदन की संशोधित तारीख जारी की गई है। इसके अनुसार बीए, बीकॉम, बीएससी, होमसाइंस, बीए मैनेजमेंट, बीबीए, बीसीए, बीकॉम आनर्स के विद्यार्थी बीस मई तक फार्म जमा कर सकते हैं। विद्यार्थी एक हजार रुपये विशेष विलंब शुल्क के साथ 21 मई को आवेदन कर सकेंगे। परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कॉपियां आठ जिलों के 225 कॉलेजों में जमा की जाएंगी। विद्यार्थी बीयू से संबद्धता प्राप्त किसी भी कॉलेज में अपनी कॉपियां जमा कर पाएंगे। नोडल कॉलेज प्रोफेसरों की टीम बनाकर उक्त कॉलेजों से कॉपियां अपने पास बुलाएगा। इसके बाद बीयू अपने गोपनीय वाहन से मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाएं लेकर आएगा। बीयू की सीमाओं से बाहर रहने वाले विद्यार्थी उपकुलसचिव के नाम से डाक के माध्यम से कॉपियों को बीयू भेज सकते हैं।

Badri Gautam

15 मई तक तय की समय सीमा

व्हाट्सएप ने कहा- शर्तें स्वीकार न की तो नहीं कर पाएंगे चैट

हरिभूमि न्यूज ▶▶| नई दिल्ली

व्हाट्सएप ने कहा कि उसके नए निजता अपडेट को स्वीकार न करने के लिए कोई भी खाता डिलीट नहीं किया जाएगा लेकिन कई हफ्तों के बाद इन विवादित शर्तों को स्वीकार न करने वाले उपयोगकर्ता अपनी चैट सूची नहीं देख पाएंगे। आखिरकार उनकी ऐप पर आने वाले फोन कॉल या वीडियो कॉल का जवाब देने की सुविधा के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी। पिछले हफ्ते फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा था कि 15 मई तक की उसकी समयसीमा तक उसकी निजता नीति अपडेट को स्वीकार न करने वाले उपयोगकर्ताओं के खाते डिलीट नहीं किए जाएंगे।

Badri Gautam

एक बार फिर याद दिलाई शर्तें

व्हाट्सएप ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि जिन लोगों को शर्तों को पढ़ने या स्वीकार करने का मौका नहीं मिला है। वह उन्हें इन शर्तों के बारे में याद दिला रहा है। कई हफ्तों के बाद लोगों को मिलने वाला यह रिमाइंडर सख्त हो जाएगा। हालांकि कंपनी ने इन रिमाइंडर के लिए तय की गयी समयसीमा के बारे में नहीं बताया।

परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ 12वीं के विद्यार्थी रख रहे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान

जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)। एक ओर जहां 12वीं की परीक्षाएं कब होंगी इसका कुछ अता- पता नहीं है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी जी-जान से परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि 12वीं के परिणामों के आधार पर ही उनका आने वाला भविष्य निर्भर करता है। खास बात यह है कि लाकडाउन के इस समय में विद्यार्थी सिर्फ बारहवीं की परीक्षा की तैयारी बस नहीं कर रहे हैं, साथ ही आने वाले समय में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करने में भी जुटे हुए हैं। किसी को नीट क्लियर करके मेडिकल क्षेत्र में जाना है, तो कोई जेईई के जरिए इंजीनियरिंग में जाना चाहता है। इसके साथ ही क्लेट, डिफेंस में जाने की तैयारियां भी चल रही हैं।

इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण लगा लाकडाउन सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। विद्यार्थी अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जिससे कहीं न कहीं मानसिक परेशानियां भी हो रही हैं। जैसे किसी को तनाव हो रहा है तो कोई सिर दर्द जैसी परेशानियों से जूझ रहा है। अच्छी बात यह है कि विद्यार्थी खुद अपनी फिटनेस को लेकर जागरूक हैं। और कैसे स्वस्थ रहा जाए इसका पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं।

12वीं मैथ्स साइंस लेकर पढ़ने वाली विश्वाती श्रीवास्तव ने बताया कि बीते दिनों उनके पिताजी कोरोना के कारण

Badri Gautam

नहीं रहे। इससे वे और उनका पूरा परिवार मानसिक रूप से बहुत तनाव में है। लेकिन परीक्षाओं को देखते हुए पढ़ाई तो करना है साथ ही खुद को फिट भी रखना है, जिससे पेपर अच्छे जाएं। इसलिए वे हर दिन एक घंटा फिजिकल वर्कआउट के लिए देती हैं। जिसमें ट्रेडमिल, योग के साथ-साथ नियमित डांस के लिए समय जरूर निकालती हैं। इतना करने से उनका दिमाग फ्रेश हो जाता है और नई ऊर्जा का अनुभव होता है। ठीक इसी तरह 12वीं की छात्रा कशिश जैन ने भी अपने पूरे दिन को एक टाइम टेबल बनाकर बांट लिया है। जिसमें हर विषय की पढ़ाई के लिए समय है तो उनके मनोरंजन, परिवार के साथ बातचीत के लिए भी पूरा समय है। कशिश का मानना है कि ऐसा करने से उनका पूरा दिन बहुत ही सरल हो गया है। जिसमें निराशा तनाव जैसी बातों के लिए अब जगह नहीं है।

सभी कर्मचारी योद्धा योजना के दायरे में, जताया सरकार का आभार

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंगलवार को शासकीय सेवकों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय हुआ है कि जो कर्मचारी कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें योद्धा योजना के अंतर्गत समस्त प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बताना होगा कि मौजूदा समय में अधिकांश विभागों के अधिकारी कर्मचारी कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं। जबकि स्वास्थ्य पुलिस नगर निगम जैसे विभागों को छोड़कर अन्य किसी भी डिपार्टमेंट के उन कर्मचारियों को योद्धा योजना का कोई लाभ नहीं था जो करोना में ड्यूटी कर रहे थे। इसके लिए लगातार कर्मचारी सरकार पर हमलावर होते रहे हैं। मांग भी उठाई है कि सरकार जब ड्यूटी करवा रही है तो कोरोना कल्याण योद्धा योजना में भी उन्हें शामिल किया जाए। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि यह निर्णय निश्चित तौर पर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर कुमार गिरी संजय लमानिया प्रदेश महामंत्री दिलीप उपाध्याय प्रदेश महामंत्री सुशील पांडे प्रदेश महामंत्री दिलीप इंगले प्रदेश मार्गदर्शक मनोज मिश्रा प्रदेश प्रवक्ता के अलावा सहकारिता समिति कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बीएस चौहान राज्य कर्मचारी संगठन प्रदेश महामंत्री हेमंत कुमार श्रीवास्तव जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदित कुमार भदोरिया सहित अन्य संगठनों के नेताओं ने सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अशोक शर्मा ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा। ज्ञातव्य है कि प्रदेश के पंचायत सचिव संगठन इस मामले को लेकर पिछले दो दिन से आंदोलन कर रहे थे जिसके दबाव कि चलते सरकार ने कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे सभी कर्मचारियों को योद्धा योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया।

Badri Gautam

उचित स्थान पर सील सिक्का और हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र करना होगा प्रस्तुत

कॉलेजों की लाइब्रेरी और लैब होगी अपग्रेड, विभाग ने प्राचार्यों से मंगाए प्रस्ताव

हरिभूमि, जबलपुर

प्रदेश के 315 कॉलेजों की लाइब्रेरी व लैब को अब उच्च शिक्षा विभाग अपग्रेड करेगा। इसको लेकर विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और जरूरत वाले कॉलेजों से प्रस्ताव मंगाए हैं। प्राचार्य को आवेदन करते समय इस बात का ख्याल रखना होगा कि विश्व बैंक परियोजना या रुसा के तहत जारी की सूची में शामिल नहीं किया गया हो। इसके लिए उन्हें उचित स्थान पर सील सिक्का और हस्ताक्षर लगाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

बढ़ाई तारीख, 15 तक कर सकेंगे आवेदन

विभाग द्वारा इसके लिए पहले छह मई तक कॉलेजों से प्रस्ताव मंगाए गए थे, लेकिन वह कोरोना कर्फ्यू के कारण प्रस्ताव नहीं भेज पाए हैं। नतीजन अब विभाग ने कोरोना कर्फ्यू के चलते तारीख बढ़ा दी गई है। लैब को अपग्रेड करने और ई-लाईब्रेरी बनाने के लिए कालेज प्राचार्य अब 15 मई तक आवेदन कर पाएंगे।

Badri Gautam

निर्धारित तिथि के बाद आवेदन निरस्त

निर्धारित तिथि बीतने के बाद विभाग पहुंचे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। विभाग ने प्राचार्यों को आदेशित किया है कि उन्हें विगत तीन वर्षों में लैब और ई-लाईब्रेरी के कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। इसके संबंध में ई-मेल कर सूचित करना होगा।

कई कॉलेजों में लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी और लैब की समुचित व्यवस्था नहीं

दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश भर में 515 पारंपरिक कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें से 200 कॉलेज विश्वबैंक व रूसा से मिलने वाले अनुदान के लिए चयनित किए गए हैं। इन्हें साल भर विभिन्न मदों से ग्रांट दिया जाता है, लेकिन 315 कॉलेजों को केवल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मिलने वाले ग्रांट का ही सहारा है। इसके चलते कई कॉलेजों में लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी और लैब की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए विभाग ने जरूरत वाले कॉलेजों से प्रस्ताव मंगाए हैं।

प्री-बोर्ड न देने वाले 10वीं के दिव्यांग पॉजिटिव फोन पर दे सकेंगे परीक्षा

नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने 10वीं की परीक्षा के लिए असेसमेंट स्कीम के तहत दिव्यांग स्टूडेंट्स को विशेष छूट दी है। इसके मुताबिक दिव्यांग स्टूडेंट्स जो स्कूल लेवल पर हुए असेसमेंट में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनका मूल्यांकन दूसरे जरिए से किया जाएगा। बोर्ड की तरफ से जारी असेसमेंट स्कीम के मुताबिक, अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट्स किसी कारण से सेशन 2020-21 में हुई स्कूल स्तर पर हुई मूल्यांकन योजना जैसे यूनिट टेस्ट, हाफ इयरली टेस्ट या प्री-बोर्ड में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनका असेसमेंट अब पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, क्विज, ओरल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए फोन या किसी और तरीके से सवाल-जवाब कर मार्क्स तय किए जा सकते हैं।

Badri Gautam

इन स्टूडेंट्स को मिलती है सुविधा

शिक्षा विभाग श्रीगंगानगर के जिला दिव्यांगता प्रकोष्ठ के समन्वयक भूपेश शर्मा ने बताया कि पीडब्ल्यूडी एक्ट-2016 के अनुसार एसडब्ल्यूएसएन कैटेगिरी के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड समेत दूसरी परीक्षाओं में कई तरह की रियायतें रहती हैं। इसी के आधार पर बोर्ड ने स्कूल लेवल पर ली गई परीक्षाओं में गैरहाजिर रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को फोन पर परीक्षा देने सहित दूसरे ऑप्शन की सुविधा दी है।

बोर्ड ने जारी की असेसमेंट स्कीम

बोर्ड की ओर से जारी की गई नई मार्क्स पॉलिसी के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सीबीएसई के नोटिफिकेशन के मुताबिक, नतीजे तैयार करने के लिए हर स्कूल को एक 8 सदस्यों वाली रिजल्ट कमेटी बनानी होगी। इसमें स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा मैथ, सोशल साइंस, साइंस और दो लैंग्वेज टीचर होंगे।

ओपन बुक से होंगी स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षाएं

भोपाल। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्नातक प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की समस्त परीक्षाएं ओपन बुक पद्धत्ति से आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने नई गाईडलाईन जारी कर दी है। जारी गाईडलाईन के अनुसार स्नातक तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जून में आयोजित होगी और जुलाई में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएगी तथा परीक्षा परिणाम अगस्त में घोषित किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय वेबसाईट पर पेपर अपलोड करेगा। पेपर अपलोड होने के बाद विद्यार्थियों को कापियां घर पर लिखनी होगी और कलेक्शन सेंटर पर कापी जमा करनी होगी। इसके अलावा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शेष प्रायोगिक परीक्षाएं ओपन बुक परीक्षा की समाप्ति के पश्चात आयोजित की जाएगी।

Badri Gautam

उच्च शिक्षा विभाग ने कहा, अतिथि लोक सेवक नहीं सिर्फ पढ़ाने के लिए इन्हें रखा

कोविड-19 में अतिथि विद्वानों की ड्यूटी लगाई गई तो प्राचार्य को मिलेगा दंड

विभाग ने संयुक्त संचालक से मांगी जबलपुर मामले की पूरी रिपोर्ट

भोपाल(आरएनएन)। उच्च शिक्षा विभाग में अस्थाई तौर पर अध्यापन के लिए रखे गए अतिथि विद्वानों को कोविड-19 में ड्यूटी करवाना अब प्राचार्य के लिए भारी पड़ जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा इनकी ड्यूटी कोरोना कार्य में लगाई गई तो कार्रवाई की जाएगी।

बताना होगा कि अतिथि विद्वानों को सिर्फ अध्यापन सत्र की निर्धारित सीमा में सिर्फ पढ़ाने के लिए नियुक्त करने का प्रावधान है। अतिथि जितने दिन पढ़ाई का कार्य करेगा उतने ही दिन उसकी वेतन बनेगी। इनके लिए बाकायदा कॉलेजों में कालखंड बनाए गए हैं। उसी के अनुसार इनका मानदेय बनता है। इसके बावजूद अनेक जिलों में इनकी ड्यूटी कोरोना मे लगा दी गई है। जबकि शासन द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रतिदिन 10 फ़ीसदी उपस्थिति के हिसाब से सिर्फ लोकसेवक ही ड्यूटी पर जाएंगे। फिर भी राजधानी भोपाल सहित विदिशा जबलपुर के अलावा अन्य जिलों में प्राचार्य ने नियम का उल्लंघन करते हुए अतिथि विद्वानों को कोविड-19 की ड्यूटी में झोंक दिया है। इस मामले को लेकर 2 दिन पहले जबलपुर में अतिथि विद्वानों ने एक कॉलेज में प्राचार्य की इस कार्यवाही का बहिष्कार किया था। उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि अतिथि विद्वान की कोविड-19 में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है।

संयुक्त संचालकों को लिखा पत्र: उच्च शिक्षा विभाग के विशेष कर्तव्य अधिकारी सुशील कुमार मडेलिया ने दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि अतिथि विद्वान की कोविड-19 में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। क्योंकि यह विभाग के लोकसेवक नहीं है। इन्हें सिर्फ अस्थाई तौर पर कॉलेज में पढ़ाने के लिए रखा जाता है। उन्होंने कहा है कि जबलपुर में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। कॉलेजों में सिर्फ अतिथि विद्वानों को 10 फ़ीसदी उपस्थिति के हिसाब से ऑफिशियल काम के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने कहा है कि अगर महाविद्यालय कार्य के अलावा इनसे कोई प्राचार्य कोरोना ड्यूटी करवाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

कई जिलों में प्राचार्य कर रहे हैं प्रताड़ित: इस संदर्भ में अतिथि विद्वान नेता डॉक्टर बीएल दोहरे का कहना है कि कई जिलों में प्राचार्य मनमानी कर रहे हैं। विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए यह सीधे अतिथि विद्वानो को कोविड-19 में ड्यूटी करने की जवाबदारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में करीब 200 अतिथि विद्वान संक्रमण का शिकार हो गए हैं। 50 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कोरोना ड्यूटी करते हुए कई अतिथि विद्वानों की मौत भी हो चुकी है। दोहरे का कहना है कि राज्य सरकार दिवंगत अतिथि विद्वानों को अन्य विभागों के सेवकों की तरह आर्थिक सहायता की व्यवस्था करे।

Badri Gautam

पेंशन में चार फीसद बढ़ेगा अंशदान

प्रदेश सरकार का निर्णय : राष्ट्रीय पेंशन योजना में अब 14% हो जाएगा अंशदान

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। प्रदेश में वर्ष 2005 के बाद भर्ती हुए 4.49 लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन योजना में सरकार अपना अंशदान चार फीसद बढ़ाएगी। अब यह 14 प्रतिशत होगा। इस कदम से सरकार पर सालाना लगभग छह सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। अभी प्रदेश में आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों के लिए सरकार 14 प्रतिशत अंशदान दे रही थी। उधर, पिछले साल किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए चमकविहीन गेहूं के बदले में सरकार राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 31 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करेगी। बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति पर कोई फैसला नहीं हो सका। किसानों के लिए आगामी वर्षों में यूरिया, डीएपी, पोटाश, सुपर फास्फेट सहित अन्य खाद का इंतजाम करने करने के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी बनाया गया है। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने दी।

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय
- पिछले साल खरीदे चमकविहीन गेहूं के 31 करोड़ रुपये नागरिक आपूर्ति निगम को देगी सरकार

एक करोड़ टन गेहूं खरीदा

मुख्यमंत्री ने बैठक से पहले मंत्रियों को बताया कि कोरोना संक्रमण के बीच समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद जारी है। अब तक एक करोड़ टन गेहूं खरीदा जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को पांच माह का निशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है।

दर बढ़ाने के पक्ष में मंत्री

वाणिज्यिक कर विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति में दुकानों के नवीनीकरण के लिए फीस पांच प्रतिशत बढ़ाने की बात रखी, जिस पर वित्त विभाग ने असहमति जताई। गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने भी वित्त विभाग के तर्क से सहमति जताई। इसके बाद तय किया गया कि नीति को और विचार कर के प्रस्तुत किया जाए।

Badri Gautam

न्यू पेंशन स्कीम • हर महीने 1600 से 5000 रु. तक फायदा

सरकार एनपीएस खाते में 10 के बजाय 14% राशि जमा करेगी

भास्कर न्यूज | भोपाल

प्रदेश के न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) वाले 4 लाख अफसरों और कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में अपने अंशदान की राशि 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दी है। इससे कर्मचारियों को हर महीने 1600 रुपए और अफसरों को 5000 रुपए तक का फायदा होगा। मंगलवार को हुई वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग इसका फैसला हुआ। बढ़ी हुई चार फीसदी राशि 1 अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में डाली जाएगी। इससे सरकार पर हर महीने लगभग 80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का अनुसमर्थन कर दिया है। इसके तहत आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के 250 अस्पतालों में लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा।

बता दें कि प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद सेवा में आने वाले अफसरों और कर्मचारियों के लिए एनपीएस स्कीम लागू की गई है। इसमें 2 लाख अफसर, कर्मचारी और 2 लाख शिक्षक हैं। इनके वेतन से हर महीने 10 फीसदी राशि कर्मचारी के वेतन से काटी जाती है और इतना ही अंश राज्य सरकार मिलाती है। यानी हर महीने कर्मचारी और राज्य सरकार के अंश की जमा हुई राशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जमा होती है, जिसे कर्मचारी पार्ट फाइनल के रूप में निकाल सकते हैं। अंतिम भुगतान रिटायरमेंट पर होता है। कर्मचारियों की इस जमा हुई राशि का 70 फीसदी हिस्से का तो उसे नकद भुगतान कर दिया जाता है, 30 फीसदी राशि पेंशन फंड के नाम पर जमा रहती है, जिससे उसे अंशदायी पेंशन का भुगतान होता है।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय

- अटल बिहारी वाजपेई सुशासन संस्थान में उपाध्यक्ष का नया पद बनाया गया है। मौजूदा महानिदेशक का पद समर्पित कर दिया गया है। संस्थान में सीईओ का एक पद एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक पद सृजित कर दिया गया है।
- भिंड जिला मालनपुर में सैनिक स्कूल सोसायटी नईदिल्ली के लिए 20.95 हैक्टेयर जमीन 1 रुपए वार्षिक लीजरेंट पर देने का निर्णय
- वर्ष 2021 से 2024 तक राज्य में डीएपी एवं यूरिया खाद की व्यवस्था के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी घोषित। मार्कफेड के माध्यम से प्रदेश में आवश्यतानुसार खाद की निर्धारित मात्रा का भंडाण किया जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार 600 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी सरकार देगी।
- कृषक मित्र चयन के लिए न्यूनतम आयु 40 के स्थान पर 25 वर्ष होगी।
- जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कर्मचारियों की अन्य विभागों में संविलियन की अवधि 30 जून 2021 तक बढ़ाई गई।

Badri Gautam

भास्कर खास • उत्तरप्रदेश के राजनपुर गांव ने पेश की मिसाल, 200 में से 173 वोट हिंदुओं के

अयोध्याः हिंदू बहुल गांव ने मुस्लिम प्रत्याशी को चुना प्रधान, 10 साल मदरसे में शिक्षक रहे हाफिज अजीमुद्दीन

भास्कर न्यूज | अयोध्या

अयोध्या का नाम सुनते ही आपके जेहन में सबसे पहले क्या आता है... शायद भगवान राम... राम मंदिर... बाबरी ढांचा या फिर दिवाली की जगमग... यहां मजहब से पहचान बनाते या ढूंढते लोग भी मिल जाएंगे...लेकिन इन्हीं लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो अयोध्या की गंगा-जमुनी तहजीब का वजूद बनाए हुए हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हिंदू बहुल राजनपुर पंचायत के लोगों ने। उन्होंने अपना प्रधान उस मुसलमान को चुना है... जो मदरसे का शिक्षक रहा है...वो गांव का इकलौता मुस्लिम परिवार भी है...उनका नाम है हाफिज अजीमुद्दीन।

दरअसल, अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले राजनपुर गांव में हाल ही में पंचायत के चुनाव हुए हैं, इनमें हाफिज को सरपंच चुना गया है। 6 उम्मीदवारों के बीच वे इकलौते मुसलमान थे और गांव हिंदू बहुल। लेकिन लोगों ने मजहब की दीवार गिराकर उन्हें सरपंच चुन लिया। गांव में करीब 600 मतदाता हैं, जिनमें सिर्फ 27 मुस्लिम हैं। ये सभी लोग हाफिज के परिवार या रिश्तेदारी के ही लोग हैं। कुल डाले गए वोटों में से हाफिज को 200 वोट मिले और वे प्रधान चुन लिए गए। जीत के बाद हाफिज कहते हैं कि गांव की प्रधानी जीतना ईद के तोहफे जैसा है। वो कहते हैं कि हिंदूओं के समर्थन ने ही उन्हें प्रधान बनाया है और अब लोगों की उम्मीद को पूरा करना उनका फर्ज है। पेशे से किसान हाफिज ने मदरसे से आलिम और हाफिज की डिग्री ली है।

हाफिज की जीत के लिए सुंदरकांड का पाठ करवाया था

हाफिज की जीत के लिए गांव वालों ने सुंदरकांड का पाठ करवाया था। मंदिरों में भजन- कीर्तन और जाप करवाए थे। हाफिज कहते हैं कि यह उन सबकी जीत है। हालांकि वे यह भी कहते हैं कि कुछ लोगों ने हिंदू-मुस्लिम करने की कोशिश भी की। दाढ़ी टोपी पर सवाल भी उठाए।

Badri Gautam

इलाज नहीं मिलने के दो मामले

उज्जैन में तड़पी ब्रेन हेमरेज की शिकार शिक्षिका और कटनी में मासूम के इलाज के लिए भटकी मां

जागरण, कटनी-उज्जैन। कोरोनाकाल में मध्यप्रदेश में दूसरी बीमारियों से पीड़ितों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार को उज्जैन के अस्पताल में वैक्सीनेशन ड्यूटी के दौरान ब्रेन हेमरेज का शिकार शिक्षिका तड़पती रही। वहीं कटनी के जिला अस्पताल के बाहर एक महिला अपने चार दिन के मासूम के इलाज के लिए भटकती रही। जानकारी के अनुसार उज्जैन में वैक्सीनेशन की टीम में कई दिनों से अपनी सेवा दे रही कोरोना वॉरियर शिक्षिका नजमा ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गई। वह बीते पांच दिन से कोरोना अस्पताल माधवनगर में भर्ती थी, उसे न तो इलाज मिल पा रहा है और न कोई अन्य अस्पताल भर्ती करने को तैयार है। मंगलवार को जैसे ही खबर मीडिया को मिली, उसे तत्काल सिविल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। नजमा की हालत बेहद नाजुक है। सिविल अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नजमा तड़पते दिखाई दे रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। नजमा को देख रहे डॉ. दीपक शर्मा ने कहा कि सिविल अस्पताल में न्यूरो सर्जन नहीं हैं और नजमा की हालत खराब हो रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल भी लगातार गिर रहा है। संभवतः उन्हें कोरोना के लक्षण भी हैं और जल्द ही उन्हें अन्य अस्पताल में इलाज के लिए लेकर जाना चाहिए। नलिया बाखल स्थित कन्या मावि की शिक्षिका नजमा पति रमजान की छत्री चौक डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी। पति रमजान खान के अनुसार डॉ. सोनाली अग्रवाल से उसका इलाज कराया। कोरोना टेस्ट भी कराया। दो दिन बाद उनके सिर में तेज दर्द हुआ। कोरोना की शंका के चलते माधवनगर अस्पताल में भर्ती किया। इसके बाद एमआरआई करवाई ■ शेष पृष्ठ 9 पर

एक हाथ में बीमार बच्चा और दूसरे हाथ में बॉटल पकड़कर अस्पताल के बाहर खड़ी रही महिला

कटनी जिला अस्पताल के बाहर एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में बच्चे को सिरिंज द्वारा दी जा रही लिक्विड दवा से भरी बॉटल पकड़े हुए एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। वीडियो में महिला व बच्चे को लेकर आया एंबुलेंस चालक बता रहा है कि वह बच्चे को कटनी जिला अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेकर आया था। इसके लिए ओपीडी पर्ची भी कटवा ली थी, लेकिन जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में उसे भर्ती नहीं किया गया। इस वजह से महिला अपने बच्चे को लेकर बाहर आ गई और जबलपुर मेडिकल कॉलेज जाने की बात कहने लगी।

Badri Gautam

इंजीनियरिंग कॉलेजों को 30 जून तक अपनी कमियां करनी होगी दूर

मापदंडों पर नहीं उतरे खरे तो सीटों में होगी कटौती

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

मप्र के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस कारण एआईसीटीई नियमों का पालन नहीं करने पर कॉलेज और पॉलिटेक्निक के आगामी सत्र 2021-22 की सीटों में कटौती कर सकता है। कॉलेजों को अपनी कमियों की पूर्ति करने के लिए 30 जून तक समय दिया है। इस सत्र में एआईसीटीई राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक पर नियमों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही करने की तैयारी में है।

प्रदेश में सागर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर सहित 151 इंजीनियरिंग कॉलेज और 61 पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित हैं। कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक में एआईसीटीई के मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष भी एआईसीटीई ने सीटों में कटौती कर दी थी, लेकिन शासन ने एक साल में मापदंडों की पूर्ति का पत्र भेजकर सभी कालेज और पॉलिटेक्निक की सीटों को बचा लिया था। अभी तक वे अपनी खामियों को दूर नहीं कर पाए हैं, इसलिए एआईसीटीई ने पत्र जारी कर जारी करते हुए कहा है कि मापदंडों का पालन नहीं करने पर संस्थानों की कुल सीटों पर कटौती की जाएगी। एआईसीटीई ने सभी सरकारी कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों को 30 जून तक अपनी पूरी जानकारी ऑनलाइन तक देने के आदेश जारी किए हैं।

20 से 30 फीसदी सीटें हो सकती हैं कम

इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 40 से 50 फीसदी पद खाली हैं। इसके अलावा क्लासरूम, लैब, उपकरण और स्टाफ रूम, कॉमन रूम और अधोसंरचना की कमियों को समय रहते पूरा नहीं किया गया, तो कॉलेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकारी और गैर सरकारी कालेज और पॉलिटेक्निक संस्थान अपने मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी सीटों में दस से बीस फीसद तक कटौती की जाएगी।

Badri Gautam

शिक्षकों द्वारा किया जा रहा सर्दी खासी, बुखार का सर्वे

Badri Gautam

ब्यावरा/ सुठालिया। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत सर्दी खासी बुखार का सर्वे शिक्षकों के द्वारा सुठालिया के ग्रामीण, नगरी क्षेत्रों में लगातार किया जा रहा है आज ग्राम शेखपुरा, तुलसीपुरा नालाझिरी, नरी, खनोटा, हासंरोद, पहाडगढ़, तथा सुठालिया अंतर्गत 15 वार्डों मे किया गया। सर्वे में शिक्षक अशोक वर्मा, मनोहर वर्मा, पुरुषोत्तम वर्मा जी एस परमार, माव सिंह सोंधिया, कैलाश नारायण कस्तूरिया, राजेश सक्सेना गोपाल दास, चेतन बाला मैडम, हरिप्रसाद नामदेव राजेंद्र शर्मा हरिओम दांगी आदि शिक्षक कार्य कर रहे है।

मप्र सरकार पेंशन के लिए देगी 4 % ज्यादा अंशदान, 5 लाख कर्मचारियों को फायदा

अभी प्रदेश सरकार पेंशन योजना में 10 प्रतिशत अंशदान दे रही है

पीपुल्स ब्यूरो • भोपाल
मो.नं. 9425078939

Badri Gautam

शिवराज कैबिनेट

मध्यप्रदेश सरकार ने अब पेंशन योजना में अपने अंशदान की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अभी तक सरकार अधिकारियों के लिए 14 प्रतिशत अंशदान देती थी। यह पेंशन योजना मप्र में 2005 से लागू हैं। बैठक में नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष का पद सृजित किया है। ये उपाध्यक्ष राज्य नीति एवं योजना आयोग के भी पदेन उपाध्यक्ष होंगे। संस्थान में सीईओ और अतिरिक्त सीईओ का भी पद मंजूर किया गया है।

यह भी निर्णय हुए

- सैनिक स्कूल सोसायटी को ग्राम मालनपुर में 20.95 हेक्टेयर शासकीय
- मार्कफेड को 2021-22 से 2023-24 तक डीएपी, काम्पलेक्स, यूरिया आदि की व्यवस्था करने 600 करोड़ की गारंटी।
- प्रदेश में कृषक मित्र चयन के लिए आयु 40 वर्ष की जगह 25 वर्ष की जाएगी।
- सीहोर के सोयाबीन प्लांट पचामा का प्लांट और मशीनरी 100% निविदा आने पर सहकारिता आयुक्त बेच सकेंगे।

सभी संवर्ग के शिक्षकों का बीमा कराएगा शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

मो.नं. 9893231237

Badri Gautam

कोरोना संक्रमण काल से सबक लेते हुए अब स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के शिक्षकों का सामूहिक बीमा कराएगा। अब स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों को भी सामूहिक बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं।

कोरोना संक्रमण सहित अन्य किसी कारण से अगर शिक्षक की मौत होती है, तब भी उसके परिवार को बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए वेतन से हर माह 200 रुपए काटे जाएंगे। वहीं रिटायर होने पर ब्याज के साथ बीमा राशि दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के इस निर्णय के बाद प्रदेश के 2.87 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षक का 5 लाख और माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक का ढाई लाख का बीमा किया जाएगा।

एजुकेशन अपडेट

उच्च शिक्षण संस्था कोविड हेल्पलाइन गठित करें :प्रो .सिंह

रिपोर्टर • IamBhopal
Mobile no. 9582826011

Badri Gautam

भोपाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कोविड-19 महामारी के प्रसार के मद्देनजर सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों से कोविड कार्य बल एवं हेल्पलाइन गठित करने, कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवहार को बढ़ावा देने, मनोचिकित्सा-सामाजिक सहायता के लिए परामर्शदाता की व्यवस्था करने के सुझाव दिए हैं। यूजीसी के अध्यक्ष प्रो. धीरेंद्र पाल सिंह ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड-19 महामारी का प्रसार निरंतर हो रहा है। महामारी की वजह से हमारी शैक्षणिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली भी बाधित हो रही है। सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान वर्तमान परिस्थितियों से उबरने के लिये विभिन्न उपाए कर सकते हैं जिनमें कोविड कार्य बल एवं हेल्पलाइन का गठन, कोविड काल में स्वच्छता, सामाजिक दूरी बनाना, हाथ धोना, परीक्षण कराना सहित वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देना शामिल हैं ।

दूरस्थ शिक्षा पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है भोज विवि : खरे

वेबिनार

भोपाल। चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) लागू होने के बाद दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में भोज मुक्त विश्वविद्यालय में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह बात भोज विवि में आयोजित वेबिनार में एक्सीलेंस कॉलेज के हिस्ट्री के प्रोफेसर प्रो. अजय प्रकाश खरे ने कही। कुलपति प्रो. जयंत सोलवलकर की अध्यक्षता में चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) पर एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया।

Badri Gautam

एनआईओएस बोर्ड परीक्षा के लिए अब 15 तक जमा होगी फीस

भोपाल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने एनआईओएस बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए फीस जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा कर 15 मई की रात तक कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फीस जमा नहीं की है, उनके लिए यह अंतिम मौका है। जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं और 12वीं कक्षा की जून 21 परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी admis.nios.ac.in के जरिए 10वीं और 12वीं कोर्स की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सुविधा

Badri Gautam

मात्र 58 आदिवासी छात्रों को मिली 50-25 हजार की राशि

जेईई, नीट आदि में कम छात्रों को मिला 'प्रोत्साहन' का फायदा

पीपुल्स ब्यूरो • भोपाल
मो.नं. 9425078939

प्रदेश के आदिवासी छात्रों के लिए शुरू की गई जेईई, नीट क्लेट सहित अन्य परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है, लेकिन इस योजना का लाभ बहुत कम छात्रों को मिल पा रहा है। केवल 58 छात्रों को ही इसका फायदा मिला है और इसमें भी मेडिकल, एनआईएफटी तथा एफडीडीआई जैसे विषयों में छात्र निकल सके हैं, जबकि 300 से ज्यादा छात्रों ने इनकी परीक्षा दी थी।

प्रदेश में जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 11 वीं एवं 12वीं में अध्ययन रहते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा जैसे जेईई, क्लेट, नीट व एम्स की तैयारी के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संभाग स्तर पर कोचिंग दिए जाने की योजना है। यह कोचिंग भोपाल, इंदौर, जबलपुर व ग्वालियर में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए कराई जाती है। कोचिंग के बाद परीक्षा में सफल होने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप सरकार 50 हजार और 25 हजार रुपए की राशि देती है। वर्ष 2020-21 में इस योजना में मात्र 58 छात्र सफल हो सके हैं, जिसमें 28 जेईई, नीट और क्लेट के हैं। कोचिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक छात्र को सरकार सालाना 10 हजार रुपए की राशि मुहैया कराती है।

इन परीक्षाओं में प्रोत्साहन राशि

पाठ्यक्रम	राशि रुपए में
जेईई-आईआईटी	50,000
एम्स मेडिकल	50,000
एनडीए	50,000
क्लेट से एनएलयूआई	50,000
नीट मेडिकल कॉलेज	25,000
एनईईटी, एनआईटी	25,000
एनआईएफटी	25,000
एफडीडीआई	25,000
आईएचएम	25,000

स्त्रोत: जनजातीय कार्य विभाग

तीन साल में मिला छात्रों को लाभ

वर्ष	छात्र संख्या	राशि
2018-19	41	21.50
2019-20	44	27.25
2020-21	58	24.00

राशि लाख रुपए में

सरकार ने नहीं उठाया कोई कदम

देश की शिक्षा नीति भेदभावपूर्ण है। ऐसे में छात्रों की नींव मजबूत नहीं होती। बड़ी सफलता की तरफ विद्यार्थी बढ़े, ये सरकार की सोच होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। प्रदेश में भारी चुनौती पूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है।

ओमकार सिंह मरकाम, पूर्व मंत्री, जनजातीय कार्य

Badri Gautam

आरजीपीवी : एग्जाम हुए नहीं, 15 सितंबर से पढ़ाई का फरमान

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) ने अभी इंजीनियरिंग की परीक्षाएं कराने की केवल घोषणा की है, लेकिन ऑल इंडिया कॉउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीआई) ने देश के सभी इंजीनियरिंग संस्थानों में 15 सितंबर से प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जब अभी तक परीक्षाएं ही नहीं हुई तो सितंबर में कक्षाएं शूरू होने पर सवाल उठने लगे हैं। एआईसीटीआई ने फीस के भुगतान करने और शिकायत प्राप्त करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। एआईसीटीई ने स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर सत्र 2021-22 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है।

BadriGautam

मालनपुर में सैनिक स्कूल के लिए एक रुपए की लीज पर भूमि

मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को मंत्रि-परिषद की हरी झंडी

भोपाल, विशेष संवाददाता।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का अनुमोदन दिया गया। मंत्रि-परिषद ने सैनिक स्कूल सोसायटी नई दिल्ली को सैनिक स्कूल की स्थापना करने के लिये ग्राम मालनपुर जिला भिण्ड की शासकीय 20.95 हेक्टेयर भूमि शून्य प्रब्याजि तथा एक रुपये वार्षिक भू-भाटक निर्धारित कर आवंटित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि परिषद ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक राज्य में डीएपीए कॉम्प्लेक्स, पोटाश एवं यूरिया उर्वरकों की व्यवस्था के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य की नोडल एजेंसी घोषित करने एवं मार्कफेड के माध्यम से प्रदेश में आवश्कतानुसार उर्वरकों की निर्धारित मात्रा की व्यवस्था के लिए अग्रिम भण्डरण करने का निर्णय लिया। इसके लिए वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक मार्कफेड को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा मार्कफेड के प्रस्ताव अनुसार 600 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

कृषक मित्र के लिए 25 वर्ष होगी आयु

मंत्रि परिषद ने भारत सरकार सहायता से संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन-आत्मा अंतर्गत प्रदेश में कृषक मित्र चयन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष करने का निर्णय लिया।

जून तक बढ़ी सहकारी बैंकों के संविलियिन की तिथि

मंत्रि परिषद ने राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (भूमि विकास बैंक) के संविलियन के लिए शेष रहे सेवायुक्तों के संविलियन की कार्यवाही पूरी करने के लिये पूर्व में लागू संविलियन योजना की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है।

Badri Gautam

राशि आवंटन आदेश का अनुसमर्थन

मंत्रि परिषद ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड को वित्त वर्ष 2020-21 में द्वितीय अनुपूरक में आवंटित की गयी राशि 1500 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयर जारी कराये जाने के संबंध में नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश का अनुसमर्थन किया। मंत्रि-परिषद में इन्हें भी मिली अनुमति।

- सोयाबीन प्र-संस्करण प्लांट पचामा जिला सीहोर स्थित औद्योगिक परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन किए जाने के लिए जारी निविदा में एच-1 द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा किया जाने का निर्णय लिया।
- राजस्व विभाग की कॉस्मो आनन्द, सिरोल, जिला ग्वालियर स्थित 5 भू-खण्ड पार्सलों के निर्वर्तन के लिए निविदाकारों की वित्तीय निविदा राशि एवं ई-नीलामी में लगाई गई राशि को उच्चतम पाए जाने से एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का अनुमोदन करते हुए निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।
- राजस्व विभाग की अल्फा नगर कॉलोनी, ग्राम मेहरा, वार्ड न.-7 जिला ग्वालियर स्थित परिसंपत्ति के निर्वर्तन के लिए जारी निविदा में निविदाकारों की वित्तीय निविदा राशि एवं ई-नीलामी में लगाई गई बोली राशि को उच्चतम पाये जाने से एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्रवाई जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया।

अतिथि विद्वानों को मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना में जोड़ने की मांग

कुरवाई। सरकारी कॉलेज में कार्यरत अतिथि विद्वानों को कोरोना की इस महामारी में मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना के अंतर्गत जोड़ने एवं कोरोना संक्रमण के कारण मरने वाले अतिथि विद्वानों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग अतिथि विद्वान महासंघ ने कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की। इस संबंध में अतिथि विद्वान महासंघ के सदस्य रजी खान ने कुरवाई पहुंचकर विधायक हरि सिंह सप्रे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक संबोधित ज्ञापन भी सौंपा जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण कुरवाई कॉलेज में पदस्थ अतिथि विद्वान रामकृष्ण तिवारी के निधन होने पर अतिथि विद्वान रामकृष्ण तिवारी के परिवार को मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है जिसमें उन्होंने कहा है कि रामकृष्ण तिवारी पिछले15 से 20 सालों से प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में अतिथि विद्वान के रूप में सेवाएं दे रहे थे और इसी के मानदेय से उनके परिवार का खर्चा चलता था उनके घर में दो बेटी हैं पत्नी एवं माता-पिता भी हैं पर उनके निधन के बाद उनके परिवार पर आर्थिक संकट रहेगा इसलिए उन्हें कोरोना योद्धा मानते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए क्योंकि नियमित कर्मचारियों के समान वह भी महाविद्यालय में कार्य कर रहे थे इस बीच में संक्रमित हुए और भोपाल अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया इसके साथ ही अतिथि विद्वान महासंघ के सदस्य रज़ी खान ने प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को भी मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना में जोड़ने की मांग की है।

Badri Gautam

शिक्षकों को इलाज के लिये मिले 5 लाख की मदद

भोपाल। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय प्रवक्ता एवं जिला अध्यक्ष भोपाल सुभाष सक्सेना ने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम करते हुए संक्रमण के शिकार बने शिक्षकों को इलाज के लिये 5 लाख की मदद देने की मांग की है। जारी बयान में उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग 25 हजार शिक्षक कोरोना ड्यूटी में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्यरत है। बावजूद इसके इनको कोरोना योद्धा नियमों में लगी शर्तों के कारण कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा इसका सरलीकरण किया जाए जिससे पीड़ितों का लाभ मिल सके।

Badri Gautam

ऑनलाइन संचालित होगी कैरियर मार्गदर्शन योजना

उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालय प्राचार्यों को जारी किया पत्र

जागरण, रीवा। कोरोनाकाल में जिले के महाविद्यालयों में चल रही कैरियर मार्गदर्शन योजना ठप रही। इस योजना को फिर से क्रियान्वित करने उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। योजना फिलहाल ऑनलाइन ही चलेगी। इसके लिए विभाग ने एडी रीवा क्षेत्र अंतर्गत महाविद्यालयों का वाट्सअप में समूह बना दिया है। इस समूह में क्षेत्र अंतर्गत महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रकोष्ठ प्रभारी व टीपीओ को जोड़ा गया है। जारी निर्देश में विभाग ने कहा है कि सभी प्राचार्य इस समूह का अवलोकन करें। यदि किसी महाविद्यालय के संबंधित अधिकारी समूह से नहीं जुड़ पाये हैं, इसकी सूचना तत्काल संबंधित समूह पर दी जाये। निर्देश में विभाग ने स्पष्ट किया कि योजना के अंतर्गत प्राचार्यों, प्रकोष्ठ प्रभारी व टीपीओ की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अतः इन दायित्वों से जुड़े प्रकोष्ठ प्रभारी व टीपीओ को बिना किसी ठोस कारण के न बदला जाये। यदि अपरिहार्य कारणों से इनके दायित्व में बदलाव किया जा रहा है तो यह बदलाव निदेशक स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन योजना को देकर ही किया जाये। गौरतलब है कि योजना के तहत महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन दिया जाता है। समय-समय पर रोजगार देने वाली कंपनियों का साक्षात्कार व सेमीनार भी महाविद्यालयों में योजना के तहत कराना होता है।

Badri Gautam

विडम्बना : कॉलेजों के अतिथि विद्वानों को कोरोना काल में दिखाया बाहर का रास्ता

हमारे प्रतिनिधि, जबलपुर| कॉलेजों में जनभागीदारी मद से रखे गए अतिथि विद्वानों को कोरोना काल में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जबकि अभी न तो सत्र समाप्त हुआ है और न ही बारह महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है। बताया जा रहा है कि कई स्वशासी महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों का वेतन भुगतान भी अटका पड़ा है। इससे अतिथि विद्वानों के सामने अच्छी खासी समस्या आन खड़ी हुई है। कॉलेजों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को पहले अधिकतम 11 माह के लिए रखकर सिर्फ कक्षाएँ संचालित होने पर ही पेमेंट दिया जाता था, लेकिन 26 जून 2018 में विभाग ने अतिथि विद्वानों को 11 माह के स्थान पर बारह माह का वेतन न्यूनतम 30 हजार प्रतिमाह और अधिकतम 15 सौ प्रति कार्य दिवस कर दिया। इसमें कक्षाएँ लेने के साथ ही एकेडमिक कार्य भी शामिल कर दिए गए। इधर अतिथि विद्वानों का कहना है कि इस समय उन्हें हटा कर कॉलेज उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, जबकि कॉलेजों के पास फंड की कोई कमी नहीं हैं।पी-2

Badri Gautam

ओपन बुक एग्जाम से पहले होगा कॉलेजों की समस्याओं का समाधान

हमारे प्रतिनिधि, जबलपुर | रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने ओपन बुक एग्जाम कराने की पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना कर्फ्यू खुलने के बाद शासन से परीक्षाएँ कराने संबंधी अनुमति मिलते ही प्रश्न पत्र पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएँगे। लेकिन उसके पहले विवि प्रशासन सभी कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक आयोजित करेगा। इस दौरान सभी से गत वर्ष परीक्षाएँ कराने के दौरान आई दिक्कतों का जायजा लिया जाएगा। ताकि इस साल कोई दिक्कत न आने पाए। इस संबंध में परीक्षा कंट्रोलर डॉ. नीलकंठ पेंडसे का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का एसआईएस कराना होगा ताकि उन तक परीक्षा संबंधित लिंक पहुँच सके। वैसे तो परीक्षा की सभी तैयारियाँ विवि प्रशासन ने गत एक माह पहले ही पूरी कर ली हैं, पेपर तैयार हो चुके हैं। इस बार परीक्षाओं के पहले विद्यार्थियों की समस्याओं को भी कॉलेज स्तर पर सुना जाएगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों पर विशेष फोकस रहेगा।

Badri Gautam

जून-जुलाई में होंगी मानकुंवर बाई कॉलेज की परीक्षाएँ

शासन के निर्देश पर स्वाशासी महाविद्यालयों की परीक्षाएँ भी ओपन बुक प्रणाली से होंगी। इसके तहत शासकीय मानकुंवर बाई कॉलेज ने परीक्षाएँ जून-जुलाई में कराने का निर्णय लिया है। इसमें स्नातक बीए/बीकॉम तृतीय वर्ष/ स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएँ जून में तो स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएँ जुलाई में आयोजित होंगी।

विश्वविद्यालय में इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना के लिए तैयारी तेज

उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन बैठक में विवि प्रशासन से ली जानकारी

जागरण, रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना होगी। इस सेंटर के जरिये नए उद्यमियों को स्टार्टअप प्रारम्भ करने में विशेषज्ञ सुझाव जैसी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। साथ ही युवाओं को नवोन्मेषी विचार के द्वारा आगे बढ़ने के लिए व्यापारिक, तकनीकी सहायता देने का प्रयास भी किया जायेगा। इस केंद्र की स्थापना के लिए मप्र शासन ने विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किए हैं। विगत माह सेंटर स्थापना की कार्ययोजना को लेकर ऑनलाइन बैठक भी हुई। इस बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने कहा कि विश्वविद्यालय को आईआईटी जैसी संस्थाओं के इन्क्यूबेशन केंद्र से सम्पर्क करना चाहिए तथा उनके अनुभव व कार्यपद्धति की जानकारी लेकर इस दिशा में काम करना चाहिए।

ऑनलाइन बैठक में रीवा विश्वविद्यालय से इन्क्यूबेशन केंद्र हेतु बनाये गए नोडल अधिकारी

डॉ अतुल पाण्डेय व कुलसचिव ने भागीदारी निभाई। इस बैठक में विश्वविद्यालय के उक्त प्रतिनिधियों ने बताया कि केंद्र की स्थापना हेतु 15सौ वर्गफीट जगह चिन्हित की जा चुकी है। साथ ही कार्य करने हेतु 6 मुख्य क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस केंद्र को आगामी वित्तीय वर्ष में 50 लाख रूपये अनुदान राशि प्रदान की जायेगी।

जून तक हो जायेगी स्थापना

इस ऑनलाइन बैठक में रीवा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने कहा कि सुपारी से निर्मित कलाकृति व खिलौने, साबुन व सेनेटाइजर निर्माण के संबंध में केंद्र द्वारा काम किया जायेगा। बैठक में कुलसचिव द्वारा आश्वस्त किया गया कि रीवा विश्वविद्यालय में जून माह तक केंद्र की स्थापना हो जायेगी। इसके अलावा दिसम्बर 2021 तक केंद्र को सभी भौतिक संसाधन उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

प्रतिवर्ष 25 नवोन्मेषी विचार करने होंगे पोषित

बता दें कि विभाग द्वारा जारी निर्देश में सेंटर की स्थापना के द्वारा प्रतिवर्ष औसत 25 नवोन्मेषी विचार या स्टार्टअप को पोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मप्र शासन द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को काफी महत्व दिया जा रहा है। ताकि बेरोजगार युवाओं के हाथ में किसी तरह कुछ रोजगार दिया जा सके। इसके लिए युवाओं को सरकार नौकरी के बजाय स्वरोजगार की तरफ मोड़ना चाहती है। इस स्वरोजगार में भी सरकार को लोन न देना पड़े, उससे बचने के प्रयास भी सरकार को करने हैं। इस लिहाज से सरकार ने विश्वविद्यालय में फिलहाल यह इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित कराने का निर्णय लिया है।

विवि के कंधों पर आयेगा वित्तीय भार

केंद्र के परिचालन व उन्नयन कार्यों की निगरानी हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कार्यकारी समिति का गठन किया जाना है। अब केंद्र की स्थापना हेतु चिन्हित जगह में अधोसंरचना भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। केंद्र संचालन वास्ते वित्तीय व मानव संसाधन की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय को ही करनी होगी। तिमाही स्तर पर केंद्र की गतिविधि का संकलन कर नोडल अधिकारी को प्रस्तुतिकरण देना होगा। इस केंद्र का संचालन का खर्च विश्वविद्यालय को स्वयं उठाना होगा। यह विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

केंद्र स्थापना के उद्देश्य

- स्थानीय स्तर पर नवाचारों को प्रोत्साहित करना एवं पल्लवन हेतु सहायता उपलब्ध कराना
- स्थानीय प्रारूपों एवं प्रादर्शों को विकसित करने उनका सुयोग्य उद्यमों से संयोजन कराना
- पेटेंट हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना
- विद्यार्थी व शिक्षकों को शोध करने अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना
- स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर तकनीकों के विकास में सहायता प्रदान करना

Badri Gautam

इग्नू का जून टर्म एंड एग्जामिनेशन स्थगित

जागरण सिटी रिपोर्टर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने देश में कहर बरपा रही कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन के चलते जून टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) को स्थगित कर दिया है। इससे पहले, परीक्षा 15 जून से शुरू होने वाली थी। विवि द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक एग्जाम का अगला शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 21 दिन पहले डिस्प्ले किया जाएगा। उसी के अनुसार, परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए ऑनलाइन लिंक खोला जाएगा। बता दें कि इग्नू ने शिक्षार्थियों को अपनी तैयारी जारी रखने और शॉर्ट नोटिस पर परीक्षा में उपस्थित होने के लिए तैयार रहने को कहा है। इससे पहले इग्नू ने टीईई के लिए असाइनमेंट सबमिशन की डेडलाइन 31 मई तक बढ़ा दी थी।

Badri Gautam

एसएटीआई के 42 विद्यार्थियों का हुआ प्लेसमेंट

विदिशा। नोयडा स्थित इनोलेब्ज़ कंपनी द्वारा संस्था से 2021 में पास आउट होने जा रहे सिविल, मेकेनिकल, आईटी, सीएसई, इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन ब्रांच के विद्यार्थियों हेतु ऑन लाइन टेस्ट आयोजित किया। संस्था संचालक डॉ. जनार्दन ने बताया कि इनोलेब्ज़ कंपनी विद्यार्थियों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं लाइव प्रोजेक्ट पर प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक प्रतिष्ठित कंपनी है। यह कंपनी अपने अन्य ग्रुपों के माध्यम से हॉस्पिटिलिटी, मीडिया, एवं चैन सप्लाई के क्षेत्रों में कार्य करती है। इनोलेब्ज़ कंपनी संस्था के चयनित छात्रों को छः माह विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों के प्रोजेक्ट पर सीधे प्रषिक्षण प्राप्त करने का अवसर दे रही है। दो वर्ष के सर्विस एग्रीमेंट पूर्ण होने पर 1,00,000 रूप्ये की बोनस राषि प्रदान करेगी, एवं इच्छुक विद्यार्थियों को कंपनी की ओर से एमबीए करने का अवसर भी प्रदान करेगी एवं प्रशिक्षण काल में कंपीटेन्सी मेंचिग के आधार पर विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर 3,60,000 के वार्षिक पैकेज पर नियुक्त किया जाना सुनिष्चित है। संस्था के ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट ऑफिसर डॉ. गोविन्द राजन चेट्टी ने बताया कि चार स्तरीय चयन प्रक्रिया में संस्था के 42 विद्यार्थियों का कंपनी में चयन हुआ है।

Badri Gautam

स्कूल में चोरों का धावा, टीवी पंखे व अन्य सामान चोरी

ग्वालियर, न.सं.

एक स्कूल के ताले चटकाकर चोरों ने बच्चों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाने के लिए टीवी तथा पंखों सहित अन्य सामान को पार कर ले गए। घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के जमाहर गांव स्थित सरकारी हाई स्कूल की है। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के जमाहर गांव में शासकीय हाईस्कूल में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर स्कूल में लगी स्मार्ट टीवी, आधा दर्जन पंखे तथा अन्य सामान पार कर दिया। वारदात का पता सुबह चला तो स्कूल प्राचार्य जगदीश पुत्र बाबूलाल अग्रवाल थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। पुलिस ने उनकी शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Badri Gautam

मकान से आधा लाख रुपए का माल पार

झांसी रोड थाना क्षेत्र के हरगोविन्द मिश्रा कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान पर धावा बोलकर चोर आधा लाख रुपए से ज्यादा का माल पार कर ले गए। वारदात का पता चलते ही पीड़ित किशन दास पुत्र सुखराम दास निवासी कम्पू थाने पहुंचा और मामले की शिकायत की। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि चोर घर में लगी करीब बीस नल की टोटियों के साथ ही टाइल्स व अन्य सामान पार कर ले गए है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

हर शासकीय सेवक के लिए बनेगी कोरोना योद्धा नीति

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा– हर शासकीय सेवक महत्वपूर्ण, एक समान बनाई जाएगी योजना, पॉजिविटी रेट घटी

पीपुल्स ब्यूरो • भोपाल
मो.नं. 9425078939

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामाजिक सहभागिता से कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में युद्धस्तर पर लगातार सभी उपाय करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रही है। जो 3 मई को घट कर 20.2% हुई और मंगलवार 11 मई को घट कर 14.78% हो गई है। यह सफलता शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकने की तीन स्तरीय रणनीति की वजह से मिल रही है। मुख्यमंत्री ने वीसी के जरिए कैबिनेट से पूर्व मंत्रियों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना के तहत प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कवर हो रही है (88%)। केवल उच्च वर्ग छूटा है। इस योजना का सभी जिलों में लाभ दिलाया जाए।

उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोरोना कार्य में लगा हुआ हर शासकीय सेवक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्य के दौरान यदि किसी शासकीय सेवक के साथ अनहोनी हो जाती है तो परिवार की सहायता के लिए एक समान योजना बनाई जा रही है। हर शासकीय सेवक को इसका लाभ मिलेगा।

गरीबों को 5 माह का नि:शुल्क राशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग के हर गरीब को 5 माह का नि:शुल्क उचित मूल्य राशन दिया जा रहा है, जिसमें से 3 माह का राशन राज्य सरकार द्वारा तथा 2 माह का केन्द्र सरकार दे रही है। इसके लिए पात्रता पर्ची, अंगूठे के निशान, आधार लिंकेज की आवश्यकता नहीं। हर गरीब को यह राशन मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। मंत्रियों को इस पर नजर भी रखनी चाहिए।

ब्लैक फंगस के इलाज की व्यवस्था की

शिवराज ने कहा कि प्रदेश कोरोना की तीसरी लहर के प्रति भी पूर्ण रूप से सचेत है तथा उसके लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कोरोना इलाज के साइड इफेक्ट ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं कैबिनेट में दिवंगत पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर, विधायक जुगल किशोर बागरी तथा कलावती भूरिया को श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन रखा गया।

कोरोना काल में 1 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन, सीएम ने दी बधाई

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संकटकाल में भी अभी तक 1 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर लिया गया है। इसके लिए सहकारिता एवं खाद्य विभाग बधाई के पात्र हैं। सरकार चमक विहीन गेहूं का भी क्रय कर रही है। बीते वर्ष की चमक विहीन गेहूं की खरीदी का 31.19 करोड़ रुपए का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया गया है।

Badri Gautam

हिंदी विवि : आरक्षण रोस्टर में विसंगतियों की आईं एक दर्जन आपत्तियां

प्रोफेसर भर्ती का अंग्रेजी अल्फाबेट की जगह हिंदी वर्णमाला में बनाया रोस्टर

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9893231237

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए हिंदी वर्णमाला के अनुसार आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है।

इसको लेकर विसंगतियों के चलते 12 लोगों के द्वारा आपत्तियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही जहां इस रोस्टर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण और विकलांग आरक्षण को भी भुला दिया गया है। वहीं, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक के लिए रोस्टर नहीं जारी होने से गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। हालांकि इस सब को नकारते हुए विवि प्रशासन का कहना है कि उन्हें हिंदी वर्णमाला में रोस्टर जारी करने के अधिकार मिला हुआ है।

आरक्षण रोस्टर अल्फाबेट में ही हो सकता है जारी

विवि द्वारा जारी रोस्टर पर आपत्ति लगाने वाले व्हिसिल ब्लोअर डॉ.

देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विवि को अध्ययन-अध्यापन कार्य हिंदी में करने के लिए मान्यता दी गई है। इसके आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसके चलते यूजीसी के आदेश भी पूर्ण रूप से मान्य होंगे और यूजीसी के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला में ही आरक्षण रोस्टर जारी किया जा सकता है। सिंह का तर्क है कि ऐसे में तो आने वाले समय में हिंदी विवि होने के नाते कोर्ट में याचिका भी अंग्रेजी के बजाय हिंदी में लगाने की बात कही जाएगी। इसी तरह संस्कृत बोर्ड एवं विश्वविद्यालय कहेगा कि उनका आरचण रोस्टर संस्कृत में बनाया जाएगा, क्योंकि वे संस्कृत में पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि जब देश में एक संविधान और एक विधान की बात सरकार करती है, तो यूजीसी द्वारा निर्धारित एक समान प्रारूप जो देश के सभी विवि में मान्य है, उसका पालन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कुलपति द्वारा इसी तरह चहेतों को लाभ दिलाने के लिए हिंदी वर्णमाला से रोस्टर जारी किया गया था, तब भी आपत्तियों के कारण भर्तियां निरस्त हो गई थीं।

नियम अनुसार रोस्टर जारी

सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए विवि को प्राप्त अधिकार और नियमों के अनुसार ही रोस्टर जारी किया गया है। इस पर आपत्तियां मंगाईं, तो स्वाभाविक है लोग अपनी जानकारी के अनुसार आपत्तियां लगा रहे हैं। सभी आपत्तियों का निराकरण कर प्रक्रिया शीघ्र आगे बढ़ाई जाएगी।

–**प्रो. रामदेव भारद्वाज**, कुलपति, अटल बिहारी हिंदी विवि, भोपाल

लॉकडाउन में कोर्ट बंद होने के बाद जारी किया रोस्टर

विवि के द्वारा जारी आपत्ति आवेदन की अवधि 10 मार्च से लेकर 15 जून के मध्य तय की गई है। न्यायालय ने इसको स्थगित कर दिया है। सिंह का कहना है कि जब कोर्ट बंद है, तब कुलपति द्वारा लॉकडाउन में अवैध तरीके से सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए नियुक्ति हेतु भर्ती करने प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विवि को प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के कितने पदों की अनुमति दी गई है। इसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए कैडरवार क्रमशः स्वीकृत पदों का 33 प्रतिशत एवं निःशक्तजनों को 6 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा विभाग के आदेश का पालन नहीं किया गया है। वहीं, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी कहीं उल्लेख नहीं है, जो गलत है।

Badri Gautam

पीपीटी के सात हजार स्टूडेंट्स की फीस लौटाने पीईबी खोलेगा लिंक

भोपाल। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने गत वर्ष प्री पालीटेक्निक टेस्ट (पीपीटी) निरस्त करने पर 21 हजार स्टूडेंट्स के पचास लाख रुपए वापस करने हैं। इसमें से 75 फीसदी छात्रों के एकाउंट नंबर और जानकारी पीईबी को मिल चुकी है, लेकिन शेष 25 फीसदी यानि लगभग सात हजार विद्यार्थी ऐसे हैं, जिनकी फीस वापस करने के लिए पीईबी के पास कोई बैंक संबंधी कोई जानकारी मौजूद ही नहीं हैं। इसलिए पीईबी उनका डाटा लेने के लिए से लिंक खोलेगा।

फीस वापस

Badri Gautam

जुलाई 2018 के बाद नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा समूह बीमा का लाभ

दिवंगत शिक्षकों को तत्काल हो लंबित स्वत्व का भुगतान

भोपाल(आरएनएन)। प्रदेश में वर्ष 2018 या इसके बाद नियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों को समूह बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री कियावत ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

इसमें उल्लेख किया गया है कि 1 जुलाई 2018 या इसके बाद नियुक्त उच्च माध्यमिक माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों को नवीन शैक्षणिक संवर्ग में शामिल करते हुए समूह बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए तत्काल राशि कटोती की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। क्योंकि यह प्रक्रिया अपनाना बहुत बेहद जरूरी है। इधर बताना होगा कि इस सुविधा को पाने के लिए वर्ष 2018 से नियुक्त शिक्षक लगातार मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि अन्य लोक सेवकों की तरह उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। जिस पर लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर द्वारा गंभीरता दिखाते हुए यह आदेश जारी करवाया गया है।

दिवंगत शिक्षकों को तत्काल हो लंबित स्वत्व का भुगतान

इधर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा एक बार फिर से शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है कि प्रदेश में करोना ड्यूटी करते हुए जो शिक्षक दिवंगत हुए हैं। उनके पीड़ित परिजनों को तत्काल लंबित स्वत्व का भुगतान किया जाए। संगठन के प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव का कहना है कि अनेक जिलों में इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण उन्हें अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में संगठन द्वारा सभी जिलों में कलेक्टरों को भी पत्र लिखा गया है। उसके बाद भी कई जिलों में इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि एक तरफ शिक्षकों को कोरोना योद्धा का दर्जा नहीं दिया गया। दूसरी तरफ दिवंगत होने के बाद उन्हें उनका ही अधिकार नहीं मिल पा रहा है।

Badri Gautam